Setting up of Indian Vaccine Corporation Limited

4038. SHRI P. UPENDRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Government have decided to set up a joint venture company, the Indian Vaccine Corporation Limited with French collaboration; and
- (b) if so, what progress Government has been made in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA):
(a) Yes, Sir. The Government decided to set up in 1989 a joint venture company called Indian Vaccine Corporation Limited (IVCOL) with a equity participation between Government of India, Indian Petrochemicals Corporation Limited and Pasteur Merieux Serums and Vaccines (PMSV) Lyon, France for the production of anti-viral vaccines against poliomyelitis, measles and rabies.

(b) The joint venture company has made considerable progress in the establishment of the manufacturing unit at manesar village of Gurgaon district, Haryana in terms of civil construction of main buildings ordering of equipment and recruitment of scientific, technical, administrative personnel. The first batch of scientists is presently undergoing training at PMSV, Lyon, France. As per the present schedule manufacturing activities under Phase-I are expected to begin in 1993.

तकनीकी कार्मिकों के लिए ग्रौर अधिक रोजगार के अवसर जुटाने की योजना

4039 श्रीमहेन्द्र सिंह लाठर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि केवल
 30 प्रतिशत प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिक
 ही रोज़गार प्राप्त कर पाते हैं श्रौर
 शेष 70 प्रतिशत या तो बेरोजगार रहते
 हैं या ग्रसंगठित क्षेत्र में काम करने
 के लिए बाध्य होते हैं;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार तकनीकी कार्मिकों भौर कुशल कर्मकारों

का देश से पलायन रोकने के उद्देश्य से उनके हेतु रोजगार के भवसरों में वृद्धि करने के लिए कोई दीर्घकालिक भ्रीर ग्रस्पकालिक योजना तैयार करने का विचार रखती है; भ्रीर

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में ज्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत चौर पेंशन (श्रीमती मारब्रेट मंत्रालय में राज्य मंत्री आ वा): (क) चूंकि अर्नेक तकनीकी व्यक्ति, रोजगार कार्यालयो में पंजीकरण नहीं करवाते ₹, इसलिए ऐसे व्यक्तियों की सही **सही प्रतिश**तता कठिन है । ऐसे व्यक्ति मिजी क्षेत्र में नौकरी कर लेते हैं ग्रथवा स्वरोजगार पसन्द कर लेते हैं। रोजनार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों में से भी कुछेक व्यक्ति निय**मित नौकरी** मिलने पर उसकी रिपोर्ट रोजमार कार्या-लयों को नहीं करते हैं।

(ख) ग्रौर (ग) विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रतिरिक्त रोजगार के ग्रवसर उत्पन्न किए जाते हैं। ग्राठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी रोजगार एक मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान ग्रौर प्रौद्योगिकी विभाग में उद्यमवृत्ति विकास की एक विशेष योजना है जिसके द्वारा विज्ञान ग्रौर प्रौद्योगिकी वाले व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंज्ञान संस्थान का बन्द किया जाना

4040 श्री विश्वासराव रामाराव पाटिल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य प्रौधोगिकी ग्रनुसंघान संस्थान. नामपुर को बन्द किए जाने का प्रस्ताव है; ग्रौर यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; ्रै (ख) निया यह भी सच है कि महाराष्ट्र ने यह आश्वासन दिया है कि संस्थान को पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में भूषि प्रदान की जाएकी; और

ं (ग) यदि हां, तो सरकार यह मुनि^{श्चित} करने क लिए त्या कदम उठा रही है कि यह संस्थान बन्द न

प्रधान मंत्री (श्री थी॰ वी० नरांसह राव): (क) सी० एस० माइ० प्रार० फील्ड/एवसटेंशन/रीजनम केन्द्रों की कार्य निष्पादकता समीक्षा के मनुसरण में प्रधान मंत्री जी की मध्यक्षता वाली सी०एस०घाइ०मार० सोसाइटी ने मन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया कि नागपुर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मनुसंधान संस्थान (सी०एफ०टी०भार०माइ०) के केन्द्र को तभी जारी रखा जा सकता है जब राज्य सरकार निम्मांकित से सहमत हो:

]. केन्द्र की पुनः स्थापना के लिए ृ**भूमि प्रदान क**रना; ग्रौर,

∏. व्ह0 प्रतिक्रत व्यय बहुन करना।

- ं (ख) जी, हा।
- (म्) महाराष्ट्र सरकार द्वारा व्यय 50 प्रतिशत बहुन करने की स्वीकृति (सहप्रति) देने के बाद ही केन्द्र की पुनःस्थापना की जा सकती है।

Detection of Errors in Computer Software Installed in WIHG, (Wadia Institute of Himalayan Geology)

4041. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that some Scientists, working in Wadia Institute of Himalayan Geology (WIHG), have detected defects in the computer software supplied by a private firm which has been in use in the WIHG since long:
- (b) whether it is also a fact that consequent to the inherent defect in the software, incorrect calculations relating to

the research have been obtained leading the work of the scientists to waste;

- (c) if so, whether Government have taken appropriate steps to quantify and evaluate the loss caused by the error and to recover compensation from the software supplier;
- (d) whether the said software is also installed and used in the computers in several other centres of the Government, including in the Defence installations;
- (e) whether the defective software has since been withdrawn from all the installations, if not, the reasons therefor; and
- (f) whether Government are contemplating to suitably reward the scientists of WIHG who detected the defects and benefited the Nation.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

- (b) A shortcoming in one software (COS inverse) function is reported to have led to incorrect calculations of data related to lattice parameters for about thirty rock samples after about four year of the systems commissioning/usage.
- (c) to (c) There has been no loss on original data and the loss has been in terms of incorrect calculations owing to defect in one software function (COS Inverse). This was brought to the notice of the vendor who have suggested an alternative solution. The fact of detection of the defect in the software function in the Wadia Institute of Himalayan Geology has been brought to the notice of all Government Departments for necessary action.
- (f) The efforts of the Scientists has been appreciated.

Technology Developed by Indian Space Research Organisation to be used as Import Substitute

4042. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the technology developed by the Indian Space Research Organisation (ISRO), both within and outside the country, is not being properly utilised by the Industry; and